साप्ताहिक

डाक पंजीयनः म.प्र./भोपाल/4-479/2019-21

RNI-MPHIN/2015/72544

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

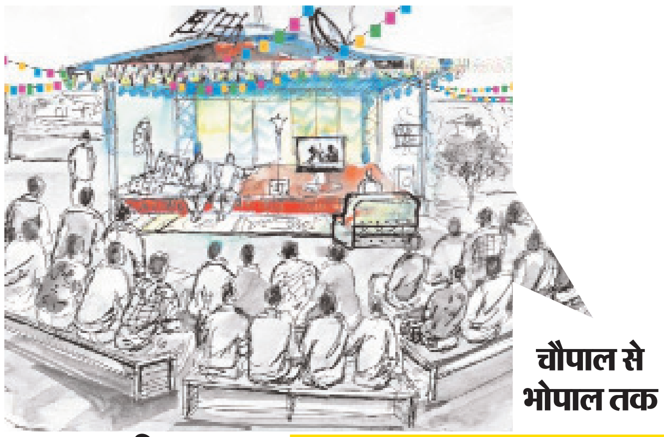

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, 17 मई 2021, वर्ष-7, अंक-07

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 8 रुपए

-प्रदेश में अभी 1.03 करोड़ टन गेहूं की हो चुकी खरीद

यूपी-बिहार, हरियाणा और पंजाब को मात देता एमपी

- » मप्र में फिर टूट सकता है गेहूं खरीद का रिकॉर्ड
- » जहां एमएसपी पर ज्यादा हुई खरीद वहां अन्नदाताओं की आय अच्छी
- » केंद्र ने प्रति क्विंटल 10 प्रतिशत चमकविहीन गेहूं लेने की अनुमति दी
- » साढ़े 12 लाख टन गेहूं के लिए प्लास्टिक बैग खरीदने के दिए आदेश
- » जिन किसानों ने अभी उपज नहीं बेची है, उन्हें एसएमएस किए जा रहे
- » 98 फीसद किसानों को उपज बेचने पहला एसएमएस किया जा चुका
- » अब तक 14,969 करोड़ रुपए के भुगतान के आदेश जारी हो गए
- » एमपी में किसानों के खातों में 11,925 करोड़ रुपए जमा भी हो चुके

मप्र का चमकविहीन गेहूं खरीदेगा केंद्र

इधर, कोरोना संकट के बीच शिवराज सरकार की पहल पर केंद्र सरकार ने प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत दी है। इसके तहत अब ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से प्रभावित गेहूं भी समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने दस फीसद तक चमकविहीन गेहूं लेने की अनुमति दी है। हालांकि, राज्य सरकार इस शर्त (सीमा) से छूट चाहती है और इसके लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार को फिर से भेजा जाएगा है। प्रदेश में इस बार गेहूं की फसल के समय ओला और अतिवृष्टि हुई थी। इससे रीवा, महाकोशल, मालवा, निमाड़, भोपाल सहित अन्य क्षेत्रों में उत्पादन और गुणवत्ता भी प्रभावित हुई। गेहूं की चमक पर सर्वाधिक असर हुआ।

अरविंद मिश्र, भोपाल

मोदी सरकार के नए कृषि कानून को लेकर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर छिड़े विवाद के बीच उपज खरीदी में एक बार फिर यूपी, बिहार, हरियाणा और पंजाब को मप्र मात देता नजर आ रहा है। इस साल भी मप्र को कृषि कर्मण अवार्ड मिलन तय है। वहीं कृषि लागत और मूल्य आयोग सीएसीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक रबी सीजन की प्रमुख फसल गेहूं इस साल देशभर में सिर्फ 43.3 लाख किसानों से ही एमएसपी पर खरीदा गया है। यह आंकड़ा भी पांच साल में सबसे अधिक है। बाकी किसान निजी क्षेत्र पर निर्भर हैं। 2020-21 में हरियाणा और पंजाब ने खरीद घटा दी है। इधर, सरकारी खरीद और डबलिंग फार्मर्स इनकम कमेटी की रिपोर्ट का विश्लेषण करें तो साफहोता है कि जिन राज्यों में सरकारी खरीद ज्यादा है वहां पर किसानों की आय अच्छी है, जिनमें एमएसपी पर कम उपज खरीदी गई वहां के किसानों की आय सबसे कम है। दरअसल, मध्य प्रदेश इस बार फिर गेहूं खरीद का रिकॉर्ड टूट सकता है। पिछले साल 1.29 करोड़ टन गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदा गया था। इस बार अभी तक 1.03 करोड़ टन गेहूं 13.12 लाख किसानों से खरीदा जा चुका है। पिछले एक सप्ताह में करीब 20 लाख टन गेहूं की खरीद हुई। इस आवक को देखते हुए संभावना जताई जा रही है कि 25 मई तक खरीदी 130 लाख टन के आंकड़े को पार कर जाएगी। मप्र में 19 अप्रैल से खरीद ने गति पकड़ी है, जो अभी तक जारी है। 19 से 25 अप्रैल के बीच 23 लाख टन के आसपास खरीद हुई। वहीं, 26 अप्रैल से दो मई तक 27 लाख टन गेहूं साढ़े चार हजार से ज्यादा खरीद केंद्रों में लिया गया। तीन से नौ मई के बीच 20 लाख टन गेहूं खरीदा गया है। अब तक 14,969 करोड़ रुपए के भुगतान के आदेश जारी हो गए हैं। किसानों के खातों में 11,925 करोड़ रुपए जमा भी हो चुके हैं। वहीं खेती-किसानी के कई मामलों में यूपी से बेहतर हालात हैं। मप्र में किसानों की औसत सालाना आय 1,16,878 रुपए है।

इनका कहना है

किसानों के हितों को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग ने केंद्र सरकार को चमकविहीन गेहूं की खरीद की अनुमति देने के लिए प्रस्ताव भेजा था। केंद्र सरकार ने अब चमकविहीन गेहूं भी दस प्रतिशत तक लेने की अनुमति दे दी है। फसल को नुकसान अधिक हुआ है।

अभिजीत अग्रवाल, प्रबंध संचालक, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम

बिहार: यह गेहूं उत्पादक राज्य जरूर है, लेकिन खरीद में सबसे निचले पायदान पर है। 2018-19 में अपने कुल उत्पादन का 0.3 फीसदी, 2019-20 में 0.5 परसेंट और 2020-21 में सिर्फ 0.1 फीसदी ही खरीद की है। मक्के की खरीद तो यहां पहले से ही एमएसपी पर नहीं होती और किसान व्यापारियों के हाथों ठगे जाते हैं। यहां के किसानों की औसत सालाना आय देश में सबसे कम सिर्फ 45,317 रुपए है।

यूपी: पिछले तीन साल से यूपी में भी गेहूं की खरीद लगातार घट रही है। 2018-19 में यूपी ने अपने कुल उत्पादन का 16.6 फीसदी, 2019-20 में 11.3 फीसदी और 2020-21 में सिर्फ 11.1 फीसदीएमएसपी पर खरीदा। इसी तरह यहां 2019-20 में धान की खरीद भी सिर्फ 56.57 लाख मिट्रिक टन की ही की गई। यहां 1 जुलाई 2020 तक सरसों की जीरो खरीद थी। किसानों की औसत सालाना आय 78,973 रुपए (सबसे कम आय वाले पांच राज्यों में शामिल) है।

हरियाणा: यहां पर (2020-21) में गेहूं की खरीद पहले के मुकाबले काफी घट कर प्रदेश के कुल उत्पादन का सिर्फ 60.3 फीसदी रह गई है। जबकि 2018-19 में यहां कुल उत्पादन का 81.6 फीसदी और 2019-20 में 74.1 फीसदी खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हुई थी। देश के करीब 25 फीसदी सरसों की खरीद अकेले हरियाणा ने की है। यहां किसानों की औसत सालाना आय देश में दूसरे नंबर पर-1,87,225 रुपए है।

पंजाब: गेहूं खरीदी में पंजाब अव्वल रहता है। लेकिन इस साल गेहूं की खरीदी में इस तमगे को मप्र छीन सकता है। 2018-19 में पंजाब सरकार ने अपने कुल उत्पादन का 71.2 फीसदी और 2019-20 में 70.7 फीसदी गेहूं की खरीद की। जबकि 2020-21 में 69.8 फीसदी यानी 127.1 लाख मिट्रिक टन खरीदा। एमएसपी पर सबसे अधिक धान की खरीद पंजाब ही कर रहा है। यहां किसानों की औसत सालाना आय देश में सबसे अधिक-2,30,905 रुपए है।

प्रधानमंत्री ने जारी की आठवीं किस्त

'अक्षय' मुहूर्त में 9.5 करोड़ किसानों को मिले दो-दो हजार

संवाददाता, भोपाल/ नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत 8वीं किस्त का वितरण किया। मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खुद कई किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफर किए। 8वीं किस्त के रूप में 9.5 करोड़ से ज्यादा किसानों को 2000-2000 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। इसके लिए केंद्र सरकार ने 20 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा राशि खर्च की है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद थे। साथ ही मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत अन्य राज्यों के सीएम और कृषि विभाग के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। वहीं कोरोना काल में पीएम मोदी ने किसानों को एक और सौगात दी। पीएम मोदी ने कहा, सरकार ने निर्णय लिया है कि कोरोना काल को देखते हुए किसान क्रेडिट कार्ड ऋण के भुगतान या नवीनीकरण की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। जिन किसानों का ऋण बकाया है, वो अब 30 जून तक ऋण का नवीनीकरण कर सकते हैं।

- ■ बंगाल के सात लाख किसानों को पहली बार लाभ
- ■ किसानों का राहत, क्रेडिट कार्ड ऋण के भुगतान या नवीनीकरण की तारीख बढ़ी
- ■ छोटी अवधि के लिए तीन लाख रुपए तक का लोन लेने वालों को लाभ मिलेगा

पीएम ने किसानों से की बात

आठवीं किस्त की राशि ट्रांसफर करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी देशभर के किसानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। मोदी ने उत्तर प्रदेश के उन्नाव के किसान अरविंद निषाद के साथ बातचीत की। इसके बाद अंडमान निकोबार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू एंड कश्मीर, मेघालय के किसानों से उनके खेती से जुड़े अनुभव जाने। पीएम मोदी ने खेती को बढ़ावा देने के लिए इन किसानों की ओर से कि जा रहे प्रयासों की सराहना भी की।

किस्तवार अब तक जारी किसान सम्मान निधि

पहली किस्त	दिसंबर	2018 3.16 करोड़
दूसरी किस्त	अप्रैल	2019 6.63 करोड़
तीसरी किस्त	अगस्त	2019 8.76 करोड़
चौथी किस्त	दिसंबर	2019 8.95 करोड़
पांचवीं किस्त	अप्रैल	2020 10.49 करोड़
छठी किस्त	अगस्त	2020 10.21 करोड़
सातवीं किस्त	दिसंबर	2020 10.15 करोड़
आठवीं किस्त	मई	2021 20,000 करोड़

इनका कहना है

मुझे संतोष है कि पश्चिम बंगाल, पंजाब और हरियाणा के लाखों किसान डायरेक्ट ट्रांसफर की इस सुविधा से जुड़े हैं। खेती में नए समाधान, नए विकल्प देने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। जैविक खेती को बढ़ावा देना ऐसे ही प्रयास है। इस प्रकार की फसलों में लागत भी कम है, ये मिट्टी और इंसान के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है और इनकी कीमत भी ज्यादा मिलती है।

नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

कृषि के नए चक्र की शुरुआत के समय इस राशि के मिलने से हमारे किसानों को लाभ होगा और वे खेती से संबंधित अपनी छोटी-छोटी आवश्यकताओं को पूर्णकर सकेंगे। कोरोना काल में किसानों को लाभान्वित करने का क्रम जारी है, जो पीएम मोदी की संवेदनशीलता को दर्शाता है। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मध्यप्रदेश के किसान भाइयों की ओर से धन्यवाद देता हूं।

शिवराज सिंह चौहान, सीएम

» कोरोना पर जारी रिपोर्ट में खुलासाः मप्र में 54 फीसदी नए केस गांवों से

» कोरोना से निपटने गांव से शहर तक बनेगी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी

» गांव में अब नो एंट्री, 90 प्रतिशत पंचायतों ने लगाया 'जनता कर्फ्यू'

गांव-गांव कोरोना

प्रमुख संवाददाता, भोपाल

मध्यप्रदेश में कोरोना ने अब गांवों को घेर लिया है। हाल ही में जारी रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि 54 फीसदी केस गांवों में मिल रहे हैं। यानी 10 में से 5 से 6 मामले गांवों के ही हैं। यही वजह है, किल कोरोना अभियान तेज करना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के गांवों में 42,155 और संदिग्ध मरीज मिले। इसमें से 5,500 से ज्यादा को फीवर क्लीनिक और केविड केयर सेंटर भेज दिया गया है। यह स्थिति तब है, जब प्रदेश में केस घट रहे हैं। एक महीने पहले तक आधे से ज्यादा केस शहरों में मिल रहे थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चेतावनी दी थी कि गांवों में लोग नहीं संभले, तो स्थिति भयावह हो जाएगी। उन्होंने कहा था कि अब गांवों में भी संक्रमण फैल रहा है। ऐसे में जरा भी ढिलाई की, तो बड़े संकट में फंस जाएंगे। अब कोरोना के जो आंकड़े आ रहे हैं, वह इसी ओर इशारा कर रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि पहली लहर में कोरोना की दस्तक गांवों में कम थी, लेकिन दूसरी लहर में गांवों में भी संक्रमण तेजी से फैल रहा है। ज्यादातर लोग जानकारी के अभाव में दम तोड़ दे रहे हैं। वजह है कि ग्रामीण इलाकों में इलाज की सुविधा भी नहीं है।

गांवों की जिम्मेदारी मंत्री-सांसद को

गांवों में संक्रमण फैलने से रोकने के लिए प्रभारी मंत्री और सांसद जिम्मेदारी सौंपी गई है। ब्लॉक व गावं स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाने के निर्देश सरकार दे चुकी है। गृह विभाग ने इस का आदेश भी जारी कर दिया है। एसडीएम, जनपद पंचायत सीईओ, सभी राजनीतिक कार्यकर्ता, समाजसेवी, जन अभियान परिषद मिलकर ग्रामीण क्राइसिस मैनजमेंट ग्रुप बनाए जाएंगे।

नगरों में ऐसी होगी कमेटी

नगरीय क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर ग्रुप का गठन किया जाएगा। इस ग्रुप के अध्यक्ष वार्ड प्रभारी अधिकारी होंगे। सांसद और विधायक के प्रतिनिधि, नगर निगम आयुक्त, मुख्य नगरपालिका अधिकारी के जनप्रतिनिधि, वार्ड के प्रतिष्ठित निजी चिकित्सक, स्वयंसेवी संगठन, जन अभियान परिषद, राजनीतिक और सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता के साथ महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्य कमेटी में होंगे।

कमेटी पर इनका होगा कंट्रोल

ब्लॉक क्राइसिस कमेटी के आदेश जिला कलेक्टर, वार्ड क्राइसिस कमेटी के आदेश संबंधित नगर निगम आयुक्त, मुख्य नगरपालिका अधिकारी और ग्राम क्राइसिस कमेटी के आदेश सीईओ, जनपद पंचायत जारी करेंगे। सभी कमेटी की महीने में कम से कम एक बैठक होना चाहिए।

एक माह में बढ़े 5 फीसदी संक्रमित

स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक एक माह में ग्रामीण इलाकों में कोरोना के केस पांच फीसदी बढ़े हैं। अप्रैल में 4,324 कोराना संक्रमित मिले थे। इसमें से 2,118 (49 प्रतिशत) मरीज ग्रामीण और 2,306 (51 फीसदी) मरीज शहरी क्षेत्रों में मिले थे, लेकिन मई में यह आंकड़ा उलट गया है। इस माह ग्रामीण क्षेत्रों से 54 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों से 46 प्रतिशत मरीज मिले। इससे साफहै कि शहरों की तुलना में गांवों में संक्रमण की रफ्तार तेज है।

गरीबों को इलाज, एंबुलेंस मुफ्त

मप्र सरकार ने कहा है कि गरीबों के लिए कोरोना का इलाज मुफ्त रहेगा। सिटीस्कैन और एंबुलेंस की सुविधा भी मुफ्त मिलेगी। सरकार ने यह भी कहा है क भोपाल से गांव में कोरोना को नहीं रोका जा सकता। यह जिम्मेदारी पंचायतों को लेनी होगी। कई पंचायतों ने अपने स्तर पर जनता कर्फ्यू लगाकर कोरोना को बढ़ने से रोका है।

किल कोरोना पार्ट-2

ग्रामीण इलाकों में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश में किल कोरोना पार्ट-2 शुरू किया गया है। जिसके तहत गांवों में मेडिसिन किट बांटना शुरू किया गया है। इसके साथ ही सदी, बुखार, जुकाम और खांसी के मरीजों की पहचान कर उन्हें इलाज मुहैया कराया जा रहा है।

गांवों में बाहरी लोगों के जाने पर प्रतिबंध

प्रदेश के गांवों में एक लाख से ज्यादा कोरोना के संदिग्ध संक्रमित चिह्नित होने के बाद 90 फीसदी गांवों ने अपने यहां जनता कर्फ्यू लगा दिया है। गांवों में आवश्यक गतिविधियां तो चालू हैं, लेकिन बाहर से आने वाले लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। उन्हें 15 दिन क्वारंटीन होने के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। इस व्यवस्था को और मजबूत तथा निष्पक्ष बनाने पुलिस, सरपंच, गांव का मुखिया, सचिव और ग्राम सहायकों की मैनेजमेंट टीम बनाई गई है। सर्दी-खांसी, बुखार सहित अन्य लक्षण मिलने पर सूचना पंच और सरपंचों के जरिए मैनेजमेंट टीम को दी जाती है। संदिग्ध संक्रमित को सबसे पहले पंचायत, आंगनबाड़ी, स्कूल भवनों में क्वारंटीन किया जा रहा है। गांव से जुड़ने वाली सड़कों पर बांस-बल्ली के बैरिकेड्स लगाए गए हैं। गांवों में प्रतिबंध लगाने में देवास, हरदा, दतिया, पन्ना, नीमच, आगर मालवा, नरसिंहपुर, भोपाल, विदिशा और रीवा जिले आगे हैं। वही धार, छिंदवाड़ा, अशोक नगर, मंडला, राजगढ़, छतरपुर और शाजापुर जिले पीछे रहे हैं।

गांवों पर सरकार का फोकस

टीकाकरण में भी रोड़े हैं, लेकिन ग्रामीणों को टीकाकरण से ही संक्रमण से बचाया जा सकता है। टीकाकरण का फोकस अब सरकार ने गांवों पर किया है। डोज पहुंचाने वैक्सीन वैन की सबसे ज्यादा जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग के पास जिलों में वैक्सीन वैन पांच से दस हैं। विभाग पल्स पोलियो, गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए किए जाने वाले नियमित टीकाकरण की व्यवस्थाओं के भरोसे गांव में कोरोना के टीके लगाने की तैयार कर रहा था, जो फेल हो गया है। नियमित केंद्रों और कोरोना वैक्सीन केन्द्रों में अंतर होगा। इन केंद्रों को नियमित टीकाकरण केंद्रों के हिसाब से नहीं बनाया जा सकता। ऐसे में संक्रमण अब शहरों से ज्यादा गांव में फैल सकता है। ऐसे में वैक्सीनेशन के लिए कैंप लगाना जोखिम भरा हो सकता है।

इनका कहना है

कोरोना संक्रमण का गांवों में प्रवेश रोकने के लिए आवश्यक है कि ग्रामीण अमला पूरी सक्रियता से काम करे। गांव में गठित समितियों द्वारा सघन सर्वे कर मेडिकल किट का वितरण किया जाए, समिति घर, ग्राम पंचायत एवं जिले को कोरोना मुक्त बनाने का संकल्प लें। जनजागृति के साथ कड़ाई भी जरूरी है। कोरोना कर्फ्यू के तहत लगाई गई पाबंदियों का पुलिस एवं प्रशासन द्वारा कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए।

कमल पटेल, कृषि मंत्री

सभी कलेक्टरों को विकास खंड, ग्राम स्तर और नगरीय क्षेत्रों में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी बनाने को कहा है। जिला स्तर पर क्राइसिस कमेटी बनाने के पहले ही आदेश दिए जा चुके थे। अब इन्हें बढ़ाकर ब्लॉक, ग्राम और नगरीय क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर किया गया है। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में हर गांव में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाए जाएंगे जिसमें ग्रुप के अध्यक्ष ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति के अध्यक्ष होंगे।

राजेश राजौरा, अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग

सोयाबीन के बीज का संकट!

» कृषि अनुसंधान संस्थानों के पास भी ब्रीडर सीड की कमी

» अब तक कृषि विभाग बीज का आकलन नहीं कर पाया

» दो साल से सोयाबीन की फसल हो रही खराब

» अन्नदाताओं को महंगा मिलेगा बाजार का बीज

संवाददाता, भोपाल

कोरोनाकाल में मध्यप्रदेश के किसानों के लिए एक और संकट आने वाला है। वह संकट है सोयाबीन के बीज का। दो साल से सोयाबीन की फसल खराब होने से इस साल बीज के लिए भारी किल्लत रहने के आसार हैं। प्रदेश में करीब 56 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन की फसल होती है और इसके लिए करीब 45 लाख क्विंटल बीज की जरूरत होगी। कृषि विभाग की निगरानी में मध्यप्रदेश बीज निगम, राष्ट्रीय बीज निगम, कृभको, नाफेड, बीज प्रमाणीकरण संस्था और बीज उत्पादक सहकारी संस्था के जरिए बीज उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन प्रतिकूल मौसम और बीमारियों के कारण इनका बीज उत्पादन कार्यक्रम भी खराब हुआ है। दूसरी तरफ निजी बीज उत्पादकों के बीज के सेंपल भी फेल हो रहे हैं। इस कारण किसानों को पर्याप्त बीज मिलना मुश्किल है।

अमानक भी मिलेगा

अधिकांश किसानों को खुले बाजार के बीज पर निर्भर रहना पड़ेगा, लेकिन वहां न केवल महंगा बल्कि अमानक बीज भी मिल सकता है। निजी बीज कारोबारी मुनाफाखोरी कर किसानों से मनमाने दाम वसूलने की तैयारी में हैं। इस समय सोयाबीन तेल में काफी तेजी है। इस तेजी का असर सोयाबीन के भाव पर भी है।

सरकार करे इंतजाम

पिछले साल खरीफ सीजन के बाद जो सोयाबीन 5300 से 5400 रुपए प्रति क्विंटल बिकी थी, वहीं अब 8 हजार रुपए क्विंटल बिक रही है। ऐसे में बीज की सोयाबीन तो इससे भी अधिक में मिलने का अनुमान है। दो साल से बेमौसम बारिश और सोयाबीन में फंगस के कारण सीड की क्वालिटी अच्छी नहीं रह पाई। ऐसे हालात में सरकार को चाहिए कि वह किसानों ने लिए रियायती दर पर बीज का इंतजाम करे।

विभाग नहीं कर पाया आकलन

अब तक कृषि विभाग भी बीज का आकलन नहीं कर पाया है। इसके बाद ही स्पष्ट होगा कि कितना मानक बीज उपलब्ध हो पाएगा। यह सही है कि इस बार सोयाबीन बीज की कमी रहेगी, लेकिन इंदौर की जरूरत पूरी हो जाएगी। आसपास के जिलों में परेशानी आ सकती है। वहीं कुछ किसानों का कहना है कि सोयाबीन खराब होने से हमने तो बड़नगर से परिचित किसानों से अच्छा बीज पहले ही ले लिया था, लेकिन कई किसानों को बीज का संकट आएगा।

प्रदेश में कृषि अनुसंधान संस्थानों के पास भी ब्रीडर सीड की कमी

प्रदेश में भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर व राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के अनुसंधान केंद्रों पर सोयाबीन का ब्रीडर सीड तैयार किया जाता है। प्रतिकूल मौसम का असर इन अनुसंधान केंद्रों के ब्रीडर सीड उत्पादन पर भी पड़ा है। यह अनुसंधान केंद्र मिलकर हर साल करीब 6 हजार क्विंटल ब्रीडर सीड उपलब्ध कराते थे, लेकिन इस साल 4 हजार क्विंटल ही हो पाएगा। ब्रीडर सीड से ही फाउंडेशन और फिर फाउंडेशन सीड से सर्टिफाइड सीड तैयार होता है जो किसानों को खेतों में उगाने के लिए उपलब्ध हो पाता है।

इनका कहना है

मुझे कुछ दिनों से अन्य राज्य से अमानक बीज लाकर प्रदेश में बेचे जाने की शिकायत मिल रही थी, जिस पर मैंने धार कृषि उपसंचालक को निर्देशित किया और हम कॉटन का अमानक बीज पकड़ने में सफल हुए। इसमें शामिल सभी दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। इसी तरह सोयाबीन के बीज में भी धांधली नहीं चलेगी।

कमल पटेल, कृषि मंत्री

किसानों को अपनी जरूरत के हिसाब से अपना बीज तैयार करना चाहिए। अपने खेत में 10 प्रतिशत रकबे में बीज उत्पादन के लिए उत्तम गुणवत्ता का बीज बोना चाहिए। गाइड लाइन के हिसाब से उसकी विशेष देखरेख, कटाई, सफाई, भंडारण करना चाहिए। भंडारण करने से पहले इनकी अंकुरण क्षमता जांचने के लिए कुछ बीज बोकर देखना चाहिए।

डॉ. मृणाल कुचलान, प्रभारी, सोयाबीन अनुसंधान संस्थान, इंदौर

इंदौर में विभिन्न शासकीय, सहकारी संस्थाओं और निजी संस्थाओं के माध्यम से 1.60 लाख क्विंटल सोयाबीन बीज उपलब्ध है। बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा इसकी टेस्टिंग की जा रही है। अब तक करीब 60 हजार क्विंटल की जांच रिपोर्ट आ चुकी है, बाकी के परिणाम आना बाकी है। इस बार सोयाबीन बीज की कमी रहेगी, लेकिन इंदौर की जरूरत पूरी हो जाएगी।

एसएस राजपूत, उप संचालक कृषि, इंदौर

देश में हर साल 7000 करोड़ का बर्बाद हो रहा राशन

» सलाहः अनाज भंडारण के हानिकारक कीटों का इस तरह करें बचाव

» गंभीर चिंतनः टीकमगढ़ कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों जाहिर की चिंता

» सिर्फ कीटों से हो रही 1300 करोड़ रुपए की हानि

संवाददाता, टीकमगढ़

भारत में हर साल 7000 करोड़ रुपए के लगभग 14 मिलियन टन खाद्यान की बर्बादी होती है। इसमें अकेले कीटों से हानि लगभग 1300 करोड़ रुपए है। भंडारण कीट द्वारा प्रमुख हानि न केवल उनके द्वारा अनाज को खाने से होती है, बल्कि संदूषण से भी होती है। फसल के कटाई के बाद सबसे जरूरी काम अनाज भंडारण का होता है। अनाज के सुरक्षित भंडारण के लिए वैज्ञानिक विधि अपनाने की जरूरत होती है, जिससे अनाज को लंबे समय तक चूहू, कीट, नमी, फफूंद आदि से बचाया जा सके। यह बात टीकमगढ़ कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक पौध संरक्षक डॉ. आरके प्रजापति और कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. बीएस किरार ने कृषि तकनीकि सम-समयाकी सलाह के दौरान कही। कृषि वैज्ञानिकों ने बताया कि प्राय- खाद्यानों में लगने वाले कीट के जो भंडारित अनाज में अधिक नमी और तापमान की दषा में अत्याधिक हानि पहुंचाते हैं। इनमें से चावल का घुन, अनाज का पतंगा या तितली, छोटी सुरसुरी, दाल भृंग, खपरा भृंग एवं अन्य कीट अत्याधिक हानिकारक है जो दानों को खाकर खोंखला कर देते हैं।

कीट प्रकोप के पूर्व बचावः गोदामों में नया अनाज रखने के पूर्व उन्हें अच्छी प्रकार साफ-सफाई करके, नीम की पत्तियां जलाकर धुआं कर लें या फिर अच्छे से कई दिन तक धूप दिखाएं। भंडारित किए जाने वाल अनाज को पूरी तरह से सुखा लें, जिसकी नमी 10 प्रतिशत के आसपास हो और वह दांतों से तोड़ने पर कड़क आवाज के साथ टूटे। अनाज की ढुलाई करने वाले वाहनों की साफ-सफाई पर अत्यधिक ध्यान रखं। अनाज को यदि बोरियों में रखना हो तो नई बोरियों का प्रयोग करं या फिर पुरानी बोरियों को गर्म पानी/डेल्टा मेथाइरिन 2.5 प्रतिशत, डब्लूपी 120 ग्राम को 3 लीटर पानी में अथवा 3 लीटर तीन महीने के अंदर पर प्रति 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल भंडारण घर पे उपयोग करें। बोरों को छाया में सुखाकर ही उनमें अनाज का भंडारण करें। बोरियों को सीधे जमीन पर न रखकर पटरों पर रखें एवं दीवारों से सटाकर न रखें। अनाज को कोठियों व गोदामों को कीड़ा रहित भली प्रकार करें या फिर एल्यूमिनियम फॉसफाइड की 7-10 गोलियां/1000 घन फीट द्वारा धुआं करें।

कीट प्रकोप के बाद उपचारः जुलाई से अक्टूबर तक अधिक नमी वाले दिनों में 15 से 20 दिन के अंतराल पर कीट प्रकोप की जांच करते रहें। यथा संभव धूप दिखाकर उसकी नमी कम करें। हवा-अवरोधी भंडारों में एल्यूमिनियम फॉसफाइड की एक गोली को 1 टन अनाज में या 7-10 गोलियां 1000 घनफुट के हिसाब से धुआं करें। इसे साथ ही भंडार को 7 दिन तक पूर्ण रूप से हवा बंद रखें। किसी प्रकार का धुआं रिहायसी क्षेत्रों में न करें।

प्रक्रिया की सावधानियांः कभी भी गैस को न सूंघें, दवा का डिब्बा हमेशा खुली हवा में ही खोलें, मुंह से दूर रखें। हवा-अवरोधी भंडारों यह हवा-अवरोधी टन के बिन में ही प्रद्युमन करें। दवा की टिकिया को कागज या कपड़े में लपेट कर रखें। ताकि अनाज में उसकी धूल ना मिलने पाए। धुआं किए गए स्थान पर धुएं की सूचना पट्टिका अवश्य रखें। अनाज को बाहर निकालने के पूर्व वहां की जहरीली हवा को निकल जाने दें। कम मात्रा में भंडारित खाद्यान्नों में, प्राकृतिक पदार्थों में नीम की पत्तियां व उसका तेल, हल्दी पाउडर, मूंगफली व सरसों का तेल, लौंग, कपूर आदि पदार्थों का प्रयोग करने से उनकी गुणवत्ता में बगैर किसी हानि के सुरक्षित रखा जा सकता है।

इनका कहना है

गेहूं में राख मिलाकर या फिर नीम की पत्तियां या उनका सूखा चूरा मिलाकर रखा जा सकता है। सूखा गेहूं बीन में भरते समय नमक की पोटली बनाकर बीच-बीच में डालने से उसमें नमी नहीं बड़ पाती। आनाज सुरक्षित रहता है। चावल को कभी भी धूप में न सुखाएं, ऐसा करने से चावल धूप में टूटता है। उसमें अजीब सी महक आ जाती है। पकाने पर ठीक से पकता भी नहीं हैं।

डॉ. आरके प्रजापति, वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र, टीकमगढ़

अनाज की पौष्टिकता कीड़ों की मलमूत्र, अंडों, मरे हुए कीटों व उनके श्वसन से उत्पन्न नमी कें कारण पैदा हुई फफूंद से नष्ट हो जाती है। देश में पैदा होने वाले अनाज का 10-12 फीसदी केवल अनुचित रख-रखाव के कारण नष्ट हो जाता है। इसलिए यह वैज्ञानिक तौर पर आवश्यक है कि किसान की कड़ी मेहनत की कमाई अनुचित रख-रखाव से खराब न हो।

पर्यावरण की पर्याप्त रक्षा करके ही धरती पर मानव अस्तित्व को रख सकते है कायम

कपिल अग्रवाल
(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

कोरोना से ठीक होने के बावजूद आम जनता की परेशानियां समाप्त होने का नाम नहीं ले रही हैं और नए रूपों में आकर कोरोना सबको हैरान कर रहा है। ताजा मामला ब्लैक फंगस का है जो कोरोना से ठीक होने वालों को बेहद तेजी से अपनी चपेट में लेकर आंखें, जबड़े आदि को अपने चपेट में ले रहा है। पिछले एक सप्ताह के भीतर देश भर में इसके सौ से अधिक मामले प्रकाश में आ चुके हैं। वैज्ञानिक इसके पीछे भी कोरोना के साइड इफेक्ट मान रहे हैं। तमाम वैक्सीनों, दावों, संभावनाओं व उम्मीदों को धता बताते हुए खतरनाक वायरस कोरोना ने एक बार फिर से मानवता पर नए रूप में धावा बोला है। इसने वैक्सीन के असर को भी काफी हद तक कम कर दिया है।

आज अनेक लोग न केवल बड़ी संख्या में इस अबूझ वायरस की चपेट में आ रहे हैं, बल्कि बड़े पैमाने पर अपनी जान से महरूम भी हो रहे हैं। हकीकत तो यही है कि डेढ़ साल बाद भी अत्याधुनिक व अति उन्नत कही जाने वाली वर्तमान मानव जाति इस मामूली से रहस्यमय वायरस के आगे नतमस्तक है। इस बार खास बात यह है कि पहले जहां यह बेहद कम तापमान पर सक्रिय हुआ था। वहीं इस बार यह औसतन 40 डिग्री के तापमान पर अवतरित हुआ है। यानी तापमान वाली पहली थ्योरी गलत साबित हुई है। इस बार इससे न केवल विभिन्न प्रकार के अजीबो-गरीब रोग उत्पन्न हो रहे हैं, बल्कि मृत्यु दर भी पहले के मुकाबले बहुत अधिक है।

कोरोना से ठीक होने के बावजूद आम जनता की परेशानियां समाप्त होने का नाम नहीं ले रही हैं और नए रूपों में आकर कोरोना सबको हैरान कर रहा है। ताजा मामला ब्लैक फंगस का है जो कोरोना से ठीक होने वालों को बेहद तेजी से अपनी चपेट में लेकर आंखें, जबड़े आदि को अपने चपेट में ले रहा है। पिछले एक सप्ताह के भीतर देश भर में इसके सौ से अधिक मामले प्रकाश में आ चुके हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन को संदेह है कि यह नया वायरस खतरनाक रूप धारण कर सकता है। भारत समेत समस्त देशों की सरकारों की पूर्ण मुस्तैदी, सजगता व युद्ध स्तरीय प्रयासों के बावजूद मामला दिनों दिन भयावह होता जा रहा है। इससे बचने की हरसंभव कोशिशें व उपाय निष्फल हो रहे हैं। ऐसे में मानव जाति के पास अपने आप को अलग थलग कर लेने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं है। संपूर्ण विश्व में इस समय इस पर निरंतर शोध व परीक्षण हो रहे हैं और हर नए शोध में नया नया निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। पहले गर्म पानी पीने व लगभग 40 डिग्री तापमान वाले कमरों में रहना इसका उपचार बताया जा रहा था, पर अमेरिका के न्यूजर्सी में यह परीक्षण भी निष्फल रहा।

अमेरिकी यूनिवर्सिटी मैरिलैंड का ताजा शोध है कि इसके प्रसार के लिए दूषित खान-पान, छुआछूत, श्वास प्रक्रिया व हमारा वायुमंडल यानी तेज हवाएं जिम्मेदार हैं। इसके लिए अलग अलग प्रकार के कृत्रिम वातावरण बनाकर जानवरों पर गहन परीक्षण जारी हैं। प्लेग के बाद यह पहली ऐसी महामारी है जिसे लाइलाज माना जा रहा है। आम जनता में घबराहट न फैले इस कारण वैश्विक स्तर पर तो लगभग सभी देशों के अधिकारिक आंकड़ों में इससे प्रभावित तथा मरने वालों की संख्या कम बताई जा रही है, पर विश्व स्वास्थ्य संगठन का ताजा अनुमान है कि इससे प्रभावितों की संख्या लाखों में पहुंच चुकी है। दुनियाभर में इस बीमारी के प्रति जागरूकता कायम करने का प्रयास किया जा रहा है।

अमेरिकी शोधकर्ताओं के नवीन मतानुसार ये वायरस अब हर प्रकार के प्राकृतिक वातावरण में बहुत तेजी से पनप रहे हैं और फिर मानव जाति में अपना प्रसार करते चले जाते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा में सभी संभव सुरक्षात्मक उपायों, लॉकडाउन, तापमान नियंत्रण आदि के बावजूद संक्रमण के मामलों में चिंतनीय तेजी जारी है। ये वायरस मूलत: पर्यावरण में उत्पन्न होकर मानव शरीर में अपना प्रसार करते हैं। इसके अलावा, अशुद्ध अथवा संक्रमित मांस खाने से भी यह मानव शरीर में पहुंचता है। शोध अध्ययन बताते हैं कि डेंगू, स्वाइन फ्लू व कोरोना जैसे सभी खतरनाक जानलेवा वायरस मूलत: जानवरों से ही आए हैं। रूस में चल रहे परीक्षणों के मुताबिक लगभग 74 डिग्री तापमान वाले नाले के पानी में इस वायरस का प्रसार बहुत तीव्र पाया गया और इसी तापमान पर बिल्कुल स्वच्छ पानी में अपेक्षाकृत कम।

इसी प्रकार मानव स्वास्थ्य एवं वायरसों पर शोध व परीक्षण कर रहे एक अमेरिकी शोधकर्ता का ताजा निष्कर्ष है कि इन वायरसों का मुख्य वाहक दूषित पर्यावरण है और मानव जाति की सुरक्षा के लिए इन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बहरहाल अभी इसके कहर से निजात की उम्मीद कम ही है, क्योंकि न तो पूर्ण रूप से इसकी प्रकृति, गुण, किस्में तथा विशेषताओं का पता चल पाया है और न ही इसका वास्तविक टीका बन पाया है। आधुनिक युग की यह सबसे उन्नत मानी जाने वाली मानव सभ्यता को अपने हर संभव पैमाने, वातावरण, परिवेश तथा परीक्षण में यह वायरस पहले के मुकाबले और ज्यादा मजबूत व बहुरंगी रूप में विद्यमान मिलता है। ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि इससे बचाव के लिए जरूरी सावधानी बरती जाए। पर्यावरण की पर्याप्त रक्षा करके ही धरती पर मानव अस्तित्व को कायम रखा जा सकता है।

सेवा के दावे पर कितना भरोसा

कोरोना के दूसरे भयावह दौर में राजनीति में अभी चिट्ठियों का दौर चल रहा है, 'लेटर बम' भेजे जा रहे हैं। इंटरनेट, वाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम के साथ मोबाइल फोन के जमाने में जब चिट्ठियां लिखना दूर की बात हो गई, तब राजनीतिक दलों को यह सबसे ताकतवर हथियार लग रहा है। राजनीतिक दल अपने विरोधी नेता को चिट्ठी लिख रहे हैं। चार राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत देश के 12 विपक्षी दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है और नौ सुझाव दिए हैं। उसमें बात सिर्फ कोरोना की नहीं है, कुछ और भी राजनीतिक सुझाव है। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी, तो उसका कड़ा-सा जवाब स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्द्धन ने भेजा, फिर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लंबी चिट्ठी लिखी, तो उससे भी लंबा जवाब भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भेज दिया। उत्तर प्रदेश में मंत्री और एमएलए मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं। देश में कोरोना की इस दूसरी लहर में हरेक दिन करीब चार लाख नए संक्रमित मरीज मिल रहे हैं और करीब चार हजार लोगों की रोजाना मौत हो रही है। यह तो सरकारी आंकड़ा है, अनुमान इससे कई गुना ज्यादा मौत होने का है, वरना गंगा, यमुना और दूसरी नदियों में लाशें बहती न दिखतीं और न ही श्मशानों व कब्रिस्तानों में मुर्दों के लिए जगह कम पड़ती। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि लोकतंत्र में सरकारों से सवाल पूछना जरूरी है और विपक्ष में बैठे राजनीतिक दलों के लिए यह सबसे मजबूत हथियार है। सवाल है, क्या सबसे जरूरी काम इस वक्त सवाल पूछना भर है और वह भी तब, जब एक राज्य में कोई पार्टी सरकार में है, तो दूसरी विपक्ष में और हर जगह हाल यही है कि अपने गिरेबान में झांकने के बजाय हर कोई दूसरे पर अंगुली उठा रहा है। इस सबके बीच पिस रहा है आम आदमी, जिसके लिए अस्पताल में न बेड है, न ऑक्सीजन और न ही वेंटिलेटर और बिना इलाज के मर जाए, तो श्मशान-कब्रिस्तान में भी जगह नहीं है। जन-नाराजगी से पीछा छुड़ाने के लिए 'पॉजिटिविटी अनलिमिटेड कैंपेन' शुरू कर दिया गया है, पर क्या सिर्फ भाषणों और प्रवचनों से पॉजिटिविटी आ सकती है?

केंद्र और राज्यों में बैठी सरकारें तो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं ही कर रही हैं, हैरानी है कि 'राष्ट्र को प्रथम' और 'समाजसेवा के लिए राजनीति' में आए हमारे राजनीतिक दल, उनके नेता और कार्यकर्ता भी इस समय कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। साल 1950 में लोकतंत्र को अपनाने वाले इस देश में आज करीब 2,300 राजनीतिक दल हैं। इनमें चुनाव आयोग में सात राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर और 59 राज्य स्तरीय पार्टी के तौर पर पंजीकृत हैं। करीब 800 सांसद हैं, 4,120 विधायक हैं, जिनमें सबसे ज्यादा भाजपा के 1,300 और कांग्रेस के 870 विधायक हैं। इसके साथ ही, हजारों की तादाद में पार्षद, पंच और सरपंच हैं। राजनीतिक दलों के सदस्यों की तादाद देखी जाए, तो दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का दावा करने वाली भाजपा के 18 करोड़ सदस्य और सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के करीब दो करोड़ सदस्य हैं। सबसे बड़े सामाजिक संगठन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के एक करोड़ से ज्यादा स्वयं सेवक हैं।

भविष्य में जैविक युद्ध की बढ़ती आशंका से निपटने के लिए करनी होगी बड़ी तैयारी

शशांक द्विवेदी

कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने पूरे देश में तबाही मचा रखी है। विशेषज्ञ तीसरी लहर की भी आशंका जता रहे हैं। ऐसे में ये सवाल उठना लाजिमी है क्या भारत किसी जैविक युद्ध का शिकार तो नहीं हुआ है जिसने अचानक चिकित्सा तंत्र को ध्वस्त करके इतनी बड़ी तबाही मचा दी हो। कोरोना वायरस कैसे और कहां से आया इसको लेकर कई तरह की बातें पिछले एक साल से की जा रही हैं, लेकिन हाल में ही इससे जुड़े कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं।

चीन के विज्ञानियों ने कोविड-19 महामारी से पांच साल पहले कथित तौर पर कोरोना वायरस को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के बारे में जांच की थी और उन्होंने तीसरा विश्व युद्ध जैविक हथियार से लड़ने का पूर्वानुमान लगाया था। अमेरिकी विदेश विभाग को प्राप्त दस्तावेजों के हवाले से मीडिया रिपोर्टों में यह दावा किया गया है।

चीनी वैज्ञानियों ने सार्स कोरोना वायरस का 'जैविक हथियार के नए युग' के तौर पर उल्लेख किया था, कोविड जिसका एक उदाहरण है। दस्तावेजों में इस बात का भी उल्लेख है कि चीन में वर्ष 2003 में फैला सार्स एक मानव निर्मित जैव हथियार हो सकता है, जिसे

आतंकियों ने जानबूझकर फैलाया हो। अमेरिकी रिपोर्ट के अनुसार चीन ने कोरोना वायरस को जैविक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है, ताकि दुश्मन देशों की अर्थव्यवस्था और चिकित्सा तंत्र को ध्वस्त कर सके। चीन, अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर को काबू में करना चाहता था इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को रास्ते से हटाना जरूरी था। वास्तव में ट्रंप चीन की तेज रफ्तार में कांटा बनकर खड़े थे। चीन ने इस वायरस का केंद्र बिंदु वुहान में ही रखा जहां दुनिया भर के लोग काम करते हैं। चीन के अन्य शहरों में इसका असर बहुत कम देखा गया। लेकिन अन्य देशों में इसने देखते ही देखते तबाही मचा दी।

दरअसल, वुहान में जब हालात बिगड़ने लगे या कहें कि बिगाड़े गए, तो दूसरे देशों के लोग अपने देश को भागने पर मजबूर हो गए। भारत और अमेरिका ने अपने नागरिकों को एयरलिफ्ट किया। इसके साथ चाइनीज वायरस भी एयरलिफ्ट हुआ और बडी संख्या में लोगों को संक्रमित करने लगा। दूसरी लहर के प्रति भारत की ही तरह अमेरिका ने भी पहली लहर में इसे हल्के में लिया और चीन की योजना बिना किसी परिश्रम के सफल हो गई। दूसरी ओर इसके फैलने के तुरंत बाद चीन की वैक्सीन बाजार में आ गई। पूरा विश्व हैरान रह गया कि अभी तो वायरस का विश्लेषण भी आरंभ नहीं हुआ था, वैज्ञानी वैक्सीन पर रिसर्च ही कर रहे थे और चीन ने वैक्सीन बेचना भी शुरू कर दिया। गौरतलब है कि चीन ने सबसे पहले वुहान में लॉकडाउन लगाया था, तो अमेरिका हैरान था कि चीन को यह कैसे पता कि लॉकडाउन से कोरोना खत्म हो सकता है। उसी लॉकडाउन में चीन ने अपने सभी नागरिकों को वैक्सीन लगा दी थी और कुछ ही महीनों में पूरे चीन में टीकाकरण का कार्य पूर्ण हो गया। चीन ने अपने लोगों में पहले ही टीका लगा कर बचाव भी कर लिया और दुनिया भर में अपना सामान भी बेच लिया। इस बीच भारत और अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देश स्वयं को इसके शिकंजे से बचाने के लिए पूरे प्रयास में जुटे हैं। यह भी देखा जा रहा है कि चीन अपने वायरस को निरंतर अपडेट कर रहा है और अपने दुश्मन देशों को हेल्थ सिस्टम में उलझाकर रखना चाहता है। पूरी आशंका है कि नए वैरिएंट अपडेट वायरस ही हो सकते हैं। अब तक के तमाम तथ्य इस बात को ही इंगित करते हैं कि इस समस्या की असली जड़ चीन ही है। ऐसे में पूरी विश्व बिरादरी को चीन के विरुद्ध एकजुट होना होगा। साथ ही, भविष्य में जैविक हथियारों या किसी भी तरह के जैविक युद्ध से निपटने के लिए भी बड़ी तैयारी करनी होगी।

किसानों के अरमानों पर फिरा पानी खरीदी केंद्रों पर भीगा लाखों टन गेहूं

- विदिशा में गिरे बड़े आकार के ओले, रायसेन व छिंदवाड़ा में भी हुई बारिश
- प्रदेश के दो दजर्न जिलों में बारिश से खरीदी केंद्रों में खुले में रखा गेहूं भीगा
- ग्वालियर में केद्र से गोदाम नजदीक था फ्रि भी बोरियां भीतर नहीं रख पाए
- बेमौसम बरिश ने जिम्मेदारों के दावों की खोली पोल

खुले में 50 लाख क्विंटल गेहूं, तूफान के आने से खलबली

इधर, मध्य प्रदेश में इस समय न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की सरकारी खरीदी चल रही है। पूरे प्रदेश में खरीदी केंद्रों पर करीब 50 लाख क्विंटल गेहूं खुले में पड़ा है और इसी बीच चक्रवाती तूफान ताउते आ धमका है। मौसम विभाग की चेतावनी है कि यह तूफान मध्य प्रदेश के कई इलाकों में तूफानी बारिश लेकर आएगा। इसके बाद से राज्य शासन के जिम्मेदार विभागों ने खरीदी रोक दी है और पूरा ध्यान खुले में रखे गेहूं को सुरक्षित तरीके से गोदामों तक पहुंचाने में लगा दिया है। प्रदेश में जबलपुर, सतना, छिंदवाड़ा, सागर, हरदा, होशंगाबाद, विदिशा, देवास, धार, इंदौर, उज्जैन, रायसेन आदि जिलों में कुल मिलाकर करीब 5 लाख टन गेहूं खुले में रखा है। मौसम विभाग की चेतावनी है कि ताउते का असर रीवा, सतना, सीधी, मंडला, जबलपुर, डिंडोरी, बालाघाट आदि इलाकों के अलावा भोपाल के आसपास के जिलों में ज्यादा असर रहेगा। मालवा और निमाड़ में भी इसका कुछ असर रहने की आशंका है। इंदौर जिले में इस समय 37 खरीदी केंद्रों पर 1 लाख क्विंटल से अधिक गेहूं खुले में रखा है।

इनका कहना है

इंदौर में हमने उन केंद्रों को चिह्नित किया है, जहां खुले में गेहूं रखा है। ट्रांसपोर्टर को इन केंद्रों की सूची दे दी गई है और वहां से सुरक्षित गोदामों में गेहूं रखवाया जा रहा है। हमारी कोशिश रहेगी कि समय रहते सारा गेहूं उठ जाए।

एमएल गजभिये, उपायुक्त सहकारिता

मौसम के बारे में हमें पहले ही अवगत करा दिया गया था। हमारा पूरा फोकस गेहूं के ट्रांसपोर्टेशन पर ही है। इसके लिए हमने इंदौर में कुछ गोदाम भी अधिग्रहित किए हैं। कुछ गेहूं खंडवा भी भिजवाया जा रहा है।

मीना मालाकार, जिला आपूर्ति नियंत्रक, खाद्य विभाग

जिन खरीदी केंद्रों पर गोदाम के अलावा खुले में जो गेहूं रखा है, वह दो दिन से उठाया जा रहा है। हर दिन में हम 7 हजार बोरी गेहूं उठा रहे थे, इसे बड़ाकर 8 हजार कर दिया है। 95 प्रतिशत गेहूं का परिवहन पहले ही कर लिया है।

अर्पित तिवारी, प्रबंधक, मार्कफेड

संवाददाता, भोपाल

मध्यप्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि का कहर जारी है। समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी जारी है। लेकिन दो दर्जन से ज्यादा जिलों में उपज खरीदी केंद्रों पर पुख्ता इंतजाम नहीं होने से लाखों मीट्रिक टन अनाज पूरी तरह से भीग गया है। जिलावार देखा जाए तो विदिशा जिले की ग्यारसपुर तहसील में जमकर बारिश हुई। इस दौरान करीब आधा घंटे तक आंवले से बड़े आकार के ओले गिरे। जहां गांवों में समथज्ञ मूल्य के गेहूं खरीदी केंद्रों पर लगभग 15 हजार क्विंटल गेहूं भीग गया। तेज आंधी के कारण घरों और गोदामों के छप्पर उड़ गए। वहीं रायसेन जिले में भी बारिश और चने के आकार के ओले गिरने से बेगमगंज क्षेत्र के 9 खरीदी केंद्रों में लगभग 34 हजार क्विंटल गेहूं भीग गया है। छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा क्षेत्र में हुई बारिश से खरीदी केंद्रों में पानी भर गया था, जिससे गेहूं की बोरियां भीग गईं।

केंद्रों पर भीगा गेहूं

धामनोद सहकारी समिति प्रबंधक नारायण प्रसाद शमाज़ ने बताया कि बारिश के कारण खुले में रखा 3028 क्विंटल गेहूं भीग गया है। इधर, कोलुआ के समिति प्रबंधक प्रकाश यादव ने बताया कि उनके खरीदी केंद्र पर करीब सौ क्विंटल गेहूं भीगा है। वहीं गुग्गैठा में तीन हजार क्विंटल गेहूं भीगा है। आंधी में गोदाम के चद्दर उड़ जाने के कारण पानी भीतर पहुंच गया। जिसकी वजह से गेहूं भीगा है।

ग्वालियर में भीगीं 4000 बोरियां

ग्वालियर जिले के जवाहर वेयर हाउस भितरवार पर बनाए गए गढ़ाजर, बागवई और मस्तूरा सोसायटी खरीद केंद्र पर खुले आसमान के नीचे करीब 4 हजार से ज्यादा बोरियां रखी गई थीं। बारिश से यह बोरियां भींगती रहीं। लेकिन केंद्र प्रभारी ने इन्हें बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया।

उम्मीदों पर फिरा पानी

जबलपुर में बेमौसम बारिश ने सिस्टम की बदइंतजामी उजागर कर दी और किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। बारिश से हजारों क्विंटल गेहूं भीग गया। बारिश से पाटन, गोसलपुर, सिहोरा के खरीदी केंद्रों में बिकने के लिए आया गेहूं पानी से भीगकर सड़ने की स्थिति में पहुंच गया। कई केंद्रों में जलभराव की स्थिति निर्मित हो गई, जिससे जमीन में रखे गेहूं के बोरे तक भीग गए। जबकि कुछ जगह किसानों ने ही तिरपाल से गेहूं को ढक दिया।

मझौली: रानीपुर खरीदी केंद्र पर 77760 क्विंटल की खरीदी की जा चुकी है। इसमें से 55036 क्विंटल गेहूं का परिवहन हो चुका है। केंद्र में 22824 क्विंटल गेहूं का स्टॉक है। खरीदी केंद्र के आसपास कम पानी गिरने तथा केंद्र प्रभारी रत्नेश भट्ट द्वारा गेहूं ढांकने बड़े-बड़े तिरपाल की व्यवस्था पहले से कर लेने से ज्यादा गेहूं को नुकसान नहीं हुआ।

गेहूं भीगने से कम होगी चमक

शिवपुरी में बारदाना की कमी के चलते खनियांधाना तहसील के बामौरकलां में समथज्ञ मूल्य पर गेहूं की खरीदी बंद थी। जिले में अचानक बारिश होने से किसानों का खुले में रखा 20 हजार क्विंटल से अधिक गेहूं भीग गया है। स्टेट सिविल सप्लाई कॉपोरेशन शिवपुरी के अधिकारी समय पर बारदाना नहीं पहुंचा पाए जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। बादल छाने के बाद भी प्रशासन ने भी उपार्जन केंद्रों की सुध नहीं ली। अधिकारियों की लापरवाही से किसानों का नुकसान हो गया है। वहीं अब बारिश से भीगे गेहूं की चमक भी कम हो जाएगी। इससे किसानों को भारी नुकसान उठाने पड़ेगा।

कटनी में लाखों का नुकसान

कटनी जिले में बारिश और तेज आंधी के चलते किसानों का काफी नुकसान हुआ था। विजयराघवगढ़ में जोरदार बारिश हुई, जिसमें खुले आसमान के नीचे रखा हजारों क्विंटल गेहूं पानी में भीग गया। केंद्र में किसानों के गेहूं रखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। खुले में किसान अपना गेहूं रखने मजबूर हैं। बारिश से ज्यादातर किसानों का गेहूं गीला हो गया, वहीं केंद्र में परिवहन के अभाव में रखा शासन का गेहूं भी पूरी तरह भीग गया है। अब इसी गेहूं का परिवहन किया जा रहा है। यही हाल खरीदी केंद्र सिंगौडी, ग्राम टीकर सहित विजयराघवगढ़ में आने लगभग सभी केंद्रों का यही हाल है। पिछले कई दिनों से रूक रूक बारिश होती रहती है। लेकिन केंद्र में किसान के आनाज रखने के लिए किसी तरह व्यवस्था की नाम की चीज नहीं है।

तौल में हो रहा घालमेल

कटनी में उपज खरीदी केंद्रों में सबसे बडी समस्या किसानों को तौल कराने में जा रही है। केंद्रों में सरकारी नियम के उलट नियम बना लिए गए हैं। तौल 50.500 किलो की होनी चाहिए, लेकिन केंद्रों में 51.200 और 51. 500 तक की तौल कराई जा रही है। जिससे किसानों को क्विंटल डेढ़ से दो किलों गेहूं ज्यादा देना पड़ रहा है। किसानों के कुछ कहने पर सवेज्यर द्वारा गेहूं खोट निकालकर किसानों की तौल रोक दी जा रही है। तौलाई में घालमेल जिले के सभी केंद्रों में हो रहा है। लेकिन किसान मजबूरन प्रभारियों के दबाव में तौल कराने मजबूर है। तौल में खेल तो हो ही रहा है। साथ में प्राकृतिक आपदा किसान परेशान हैं।

उज्जैन में घुना गेहूं खरीदना पड़ा महंगा

उज्जैन। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी केंद्र पर समिति प्रबंधक, सर्वेयर और किसान की मिलीभगत से नॉन एफएक्यू गेहूं खरीदी का मामला सामने आया है। इसके बाद खरीदी के नोडल अफसर अपर कलेक्टर ने संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। खरीदी केंद्र पर गड़बड़ी के बाद एफआईआर का दूसरा मामला है। पहले दताना के सर्वेयर के खिलाफ किसान से रुपए मांगने के आरोप में एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। केंद्रों की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए कलेक्टर आशीष सिंह ने समिति बनाई है। खरीदी के नोडल अफसर अपर कलेक्टर अवि प्रसाद, एसडीएम तराना एकता जायसवाल, जिला आपूर्ति नियंत्रक मोहन मारू और उपायुक्त सहकारिता ओपी गुप्ता ने तराना तहसील के गेहूं खरीदी केंद्र सामगी, कनार्दी का निरीक्षण किया। किसान हाकम सिंह पिता सिद्धनाथ के 85 क्विंटल गेहूं में जीवित किट लगा घुन वाला गेहूं खरीदना पाया गया। इसके आधार पर अपर कलेक्टर ने समिति प्रबंधक ओमप्रकाश वर्मा, समिति सर्वेयर राहुल अरवाल के खिलाफ थाना तराना में एफआईआर दर्ज करवाई है।

पटवारी करेंगे जांच: खराब गेहूं खरीदी करने, निगरानी नहीं रखने, कोई कार्रवाई नहीं करने पर सामगी के प्रशासक सहकारिता निरीक्षक संतोष साकलिया को निलंबित करने का प्रस्ताव भेजा है। खराब गेहूं समिति से जब्त कर वेयर हाउस तराना में सुपुर्द किया है। जिला आपूर्ति नियंत्रक का कहना है कि किसान के संबंध में संबंधित पटवारी और आरआई जांच करेंगे कि उन्होंने कितने रकबे में गेहूं की बोवनी की थी। उनकी पैदावार कितनी हुई थी।

गांवों में गोदाम बनाने किसानों को मिलेगी 1.75 लाख सब्सिडी

संवाददाता, भोपाल

किसानों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने बहुत सी योजनाओं बनाई हैं और किसानों को उस योजना का पता न होने के कारण पात्र हितग्राही भी उस योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं। दरअसल, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत भंडार गृह यानि गोदाम बनाने के लिए भी किसानों को सरकार की ओर से अनुदान दिया जा रहा है जिससे किसान उत्पादित वस्तुओं का भंडारण कर सुरक्षित रख सकें। इस योजना के तहत अलग-अलग राज्यों में किसानों को अलग-अलग सब्सिडी दी जाती है। अभी मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों से 50 मीट्रिक टन प्याज का भंडार गृह (गोदाम) बनाने के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक किसान इसमें आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकता है। यह आवेदन जिले के दिए हुए लक्ष्य के अनुसार किया किए गए हैं। भंडार गृह एवं के लिए आवेदन उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मध्यप्रदेश के द्वारा आमंत्रित किए गए हैं। किसान यदि योजनाओं के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए उद्यानिकी एवं विभाग मध्यप्रदेश पर देख सकते हैं।

पात्रता रखने वाले हितग्राही

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राज्य के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के 51 जिले के किसानों के लिए है, और राज्य के सभी जिलों को मिलाकर 425 प्याज भंडारण का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य में अनुसूचित जाति के किसानों के लिए 173 तथा अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए 252 प्याज भंडारण का लक्ष्य है।

सभी जिलों में योजना

यह योजना मध्य प्रदेश के सभी जिलों में लागू की गई है। सरकार ने राज्य के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसानों के लिए लक्ष्य जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त सामान्य अथवा पिछड़े वर्ग के किसान अभी योजना के लिया आवेदन नहीं कर पाएंगे।

प्याज गोदाम पर मिलेगी सब्सिडी

योजना के अनुसार लाभार्थी किसानों को गांवों में प्याज भंडार गृह पर 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग के तरफ से 50 मीट्रिक टन क्षमता वाले भंडारण के लिए अधिकतम 3,50,000 /रुपए की लागत तय की गई है। इसमें किसानों को लागत की अधिकतम 1,75,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। इससे किसानों पर कोई आर्थिक भार नहीं आएगा।

आवश्यक नियम और शर्तें

पात्र हितग्राही किसान को कम से कम दो हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्याज का उत्पादन करना आवश्यक है, और इसके साथ ही प्याज भंडारण का उपयोग किसी अन्य कामों के लिए नहीं किया जा सकता है। प्याज भंडारण गृह का निमाज्ण एनएचआरडीएफद्वारा जारी डिजाइन/ड्राइंग एवं निर्धारित मापदंड अनुसार होना चाहिए एवं आशय पत्र जारी होने के बाद अधिकतम छह माह के भीतर प्याज भंडार गृह का निर्माण पूर्ण करना आवश्यक होगा।

कब तक मिलेगी सब्सिडी

पात्र हितग्राही किसानों द्वारा निर्मित प्याज भंडारण गृह का शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन के लिए जिले के उप/सहायक संचालक उद्यान की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति गठित की जाएगी, जिसमें समिति के मूल्यांकन एवं भौतिक सत्यापन तथा अनुशंसा के आधार पर संबंधित किसान को अनुदान की राशि का भुगतान नियमानुसार एमपीएगो द्वारा डीबीटी के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में किया जाएगा।

राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत मप्र में स्थापित होंगी 32 इकाइयां

बांस की खेती से चमकेगी किसानों की किस्मत

भोपाल। किसानों की आय बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने राष्ट्रीय बांस मिशन मिशन की शुरुआत की है। पीएम नरेंद्र मोदी चाहते हैं देशी उत्पाद आगे बढ़े और दुनिया भर में इसका निर्यात हो। दरअसल, किसानों की आय दोगुनी के करने के लिए केंद्र के साथ मप्र की शिवराज सरकार लगातार प्रयास कर रही है। किसानों लिए नई-नई योजनाओं का ऐलान कर रही है। उनमें से ही एक योजना है राष्ट्रीय बांस मिशन। मोदी सरकार ने यह मिशन देश के 9 राज्य मध्य प्रदेश, असम, कर्नाटक, नागालैंड, त्रिपुरा, ओडिशा, गुजरात, उत्तराखंड व महाराष्ट्र में शुरू किया है। अब इधर, मध्यप्रदेश में बांस उगाने वाले किसानों की आय बढ़ाने के लिए बांस उत्पादों की उत्पादन इकाइयां मंजूर कर एक करोड़ 22 लाख से ज्यादा का अनुदान जारी किया गया है। इस वर्ष प्रदेश में 32 आधारित इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।

दावा किया जा रहा है कि बांस रोपण के प्रारंभिक 3-4 वर्षों में सफल होने के लिए किसानों द्वारा कृषि-वानिकी मॉडल को अपनाना होगा। विशेषज्ञों का हना है कि बांस उद्योग को फीडस्टॉक प्रदान करने के लिए बड़े पैमाने पर खेती योग्य बंजर भूमि पर रोपण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बांस के पूर्ण उपयोग के लिए एकीकृत प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयां यानी शून्य अपशिष्ट नीति से देश में बांस के अधिकतम उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।

प्रति एकड़ एक लाख की आमदनी: राज्य बांस मिशन के अधिकारियों ने बताया कि किसानों की आय दोगुनी करने और पर्यावरण सुधार के लिए मिशन द्वारा कृषकों की भूमि पर लक्ष्य के अनुरूप पिछले वर्षों में 15 लाख से अधिक बांस के पौधे रोपित किए गए हैं। जबकि केवल 2020 में 3500 हेक्टेयर निजी क्षेत्र में बांस रोपण करवाया गया है। रोपण के चार वर्ष बाद बांस के भिररे काटने लायक हो जाते हैं और इससे किसान को सालाना प्रति एकड़ एक लाख रुपए से अधिक की आमदनी हो सकेगी।

सब्सिडी का भी प्रावधान: राष्ट्रीय बांस मिशन योजना में बांस उत्पादों के उद्योग लगवाने के लिए बैंक से सब्सिडी का भी प्रावधान है। इच्छुक उद्यमियों की बैंकेबल प्रोजेक्ट भी मिशन द्वारा निःशुल्क बनाया गया है। बैंकों की अनुशंसा पर अभी तक कई इकाइयां स्वीकृत कर एक करोड़ से ज्यादा का अनुदान जारी किया जा चुका है। इसके अलावा उद्यमियों के प्रोजेक्ट के लिए संबंधित बैंकों की सहमति भी प्राप्त हो गई है।

इनका कहना है

देश में मध्यप्रदेश एक मात्र ऐसा राज्य है जहां बांस उत्पादकों की उत्पादन इकाइयों का कार्य प्रारंभ हुआ है। बांस मिशन से जुड़े अधिकारियों के सकारात्मक प्रयास करने के कारण सफल परिणाम सामने आए हैं। इस दिशा में प्रयास और तेज करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

विजय शाह, वन मंत्री

इंदौर में बन रहा देश का सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट

इंदौर। शहर के ट्रेंचिंग ग्राउंड में बनाए जा रहे देश के सबसे बड़े सीएनजी प्लांट की क्षमता शुरुआत में 12000 किलो प्रतिदिन गैस उत्पादन की रहेगी, लेकिन बाद में उसे बढ़ाया जा सकेगा। यह क्षमता 16000 किलो प्रतिदिन तक बढ़ाई जा सकेगी। इस गैस का उपयोग लोक परिवहन के वाहनों को चलाने में होगा। प्लांट संचालित करने वाली निजी बायो सीएनजी वाहनों को गैल द्वारा तय कीमतों के अनुसार गैस बेचेगी। इंदौर की सिटी बसों को भी चलाने में इसी गैस का उपयोग होगा। इससे अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लि. की सिटी बस संचालन लागत घटेगी, बल्कि शहर के पर्यावरण को भी फायदा होगा। नगर निगम और कंपनी के बीच हुए अनुबंध के अनुसार कंपनी निगम को बाजार से पांच रुपए सस्ती दरों पर बायो सीएनजी बेचेगी।

इनका कहना है

चोइथराम मंडी के पास स्थापित सीएनजी प्लांट से उत्पादित गैस का उपयोग सिटी बसों में हो रहा है। ट्रेंचिंग ग्राउंड में बनाया जा रहा प्लांट न केवल सबसे बड़ा प्लांट होगा, बल्कि सबसे आधुनिक प्लांट भी होगा। यहां की मशीनरी उन्नत किस्म की होगी। प्लांट के लिए निगम ने करीब 10 एकड़ जमीन कंपनी को लीज पर दी है।

संदीप सोनी, अपर आयुक्त, नगर निगम, इंदौर

प्लांट के लिए कुछ मशीनें और कंपोनेंट्स यूनाइटेड किंगडम और कुछ जर्मनी से आने हैं। भविष्य में जब भी मशीनें-उपकरण इंदौर आएंगे, तेजी से प्लांट निर्माण शुरू होगा। इससे पहले निगम एक बायो सीएनजी प्लांट चोइथराम मंडी के पास स्थापित कर चुका है। उक्त प्लांट भी सफलता पूर्वक संचालित किया जा रहा है।

असद वारसी, वेस्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ननि, इंदौर

कंपनियों ने 40 दिन में दो बार घटा दिए दाम, अब दूध के भाव ने किसानों के निकाले आंसू

मुरैना में खली 33 रुपए किलो और दूध 30 रुपए प्रति लीटर

संवाददाता, मुरैना

दुग्ध पावडर और घी बनाने वाली कंपनियों ने 40 दिन में दो बार दूध के दाम तीन रुपए लीटर और कम कर दिए हैं। लगातार भाव कम होने का असर यह है कि दूध उत्पादक किसान अब कंपनियों को कम दूध दे रहे हैं। सर्दी के सीजन में दुग्ध पदार्थ निर्माता कंपनियों को मुरैना जिले से प्रतिदिन 8 लाख लीटर दूध की आपूर्ति होती है। रेट कम होने से यह आपूर्ति घटकर दो लाख लीटर रह गई है। किसानों का कहना है कि खली के दाम 33 रुपए किलो हैं, लेकिन उन्हें दूध का भाव 30 रुपए लीटर दिया जा रहा है, इसलिए अब गांव में ही दूध का घी और छाछ बनाएंगे। लॉकडाउन के चलते किराना बाजार बंद होने से घी व मिल्क पावडर के डिब्बों की बिक्री कम हो गई है। ऐसे में मालनपुर, धौलपुर, अलीगढ़ और कोसी की कंपनियों ने दूध खरीदना कम कर दिया है। साथ ही दूध के दाम 36 रुपए लीटर से घटाकर 30-32 रुपए लीटर कर दिए हैं। भुगतान भी महीनेभर बाद किया जाता है। इसलिए किसानों ने प्राइवेट कंपनियों को दूध देना कम कर दिया है। किसानों का कहना है कि दूध 30 रुपए लीटर बिके और पशु को खली 33 रुपए किलो के भाव की खिलाई जाए तो दूध के कारोबार में मुनाफा कैसे होगा।

मार्च में घटाए थे 11 रुपए

दुग्ध उत्पाद बनाने वाली कंपनियों ने 29 मार्च को दूध के दाम 47 रुपए से घटाकर 36 रुपए कर दिए थे, तब दूध देने वाले लोगों को 11 रुपए लीटर का घाटा उठाना पड़ा था। 40 दिन बाद कंपनियों ने फिर से मनमानी करते हुए दूध के दाम 36 से घटाकर 32 व 33 रुपए लीटर कर दिए हैं। कंपनियों का तर्क है कि लॉकडाउन के कारण बाजार से घी व दूध पावडर की मांग नहीं आ रही है। इसलिए प्रॉडक्शन कम करना पड़ा है। प्रॉडक्शन डाउन होने के कारण दूध के रेट घटाना पड़े हैं।

भुगतान लेट तो रेट 1 रुपए अधिक

मालनपुर की पारस कंपनी इस समय 33 की जगह 34 रुपए लीटर के भाव से दूध खरीद रही है, लेकिन इस कंपनी का भुगतान डेढ़ महीने बाद मिलने के कारण चिलर मालिक पारस कंपनी को दूर देने से तौबा कर रहे हैं। मालनपुर को नोवा व धौलपुर की भोले बाबा कंपनी 32 से 33 रुपए लीटर के रेट दे रही हैं, लेकिन उनका भुगतान तय समय पर होता जाता है।

इनका कहना है

कंपनियों ने दूध के रेट फिर से घटा दिए हैं। अब 30 से 32 रुपए लीटर के भाव से दूध का भुगतान किया जा रहा है। दूसरी बार रेट गिरने से दूध उत्पादक किसानों ने समितियों को दूध देना कम कर दिया है।

शिव सिंह गुर्जर, संचालक, चिलर प्लांट, मुरैना

पानी नहीं मिलने से सूखने की कगार पर मूंग की फसल

टिमरनी के आक्रोशित अन्नदाता बोले- राज्य सरकार को करनी होगी किसानों के नुकसान की भरपाई

टिमरनी। ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल में नहर विभाग द्वारा पानी का सही आवंटन न कर पाने की वजह से टेल क्षेत्र के कई किसानों की मूंग की फसल सूखने से की कगार पर पहुंच गई है। जबकि सीजन की शुरुआत में नहर विभाग द्वारा प्रसारित किया गया था, कि इस बार पानी हेड टू टेल दिया जाएगा। टेल क्षेत्र के किसानों ने नहर विभाग को चेतावनी देते हुए कहा, कि अगर फसलें सूखी तो सरकार को क्षेत्र का सर्वे कर नुकसान की भरपाई करनी होगी। क्योंकि नहर विभाग ओर प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल, टिमरनी विधायक संजय शाह के कहने हम ग्रीष्म कालीन मूंग के लिए 50 दिन पर्याप्त पानी देंगे के वादे पर ही हमने मूंग की बोवनी की थी। दीपगांव के किसान विजय मीणा ने कहा, कि अगर पानी नहीं था तो हमें आश्वासन नहीं देना था और अगर पानी था तो उसका बंटवारा प्रबंधन ठीक तरह से करना था। किसानों ने कहा, कि तवा डैम के जलस्तर का पुराना डेटा है उसको सार्वजनिक किया जाए व उसके आधार पर तय किया जाए की डैम में शेष कितने दिन का पानी बचा है व टेल क्षेत्र के लिए विशेष नियम बनाकर संबंधित अफसरों की ड्यूटी लगाकर वह पानी टेल क्षेत्र तक पहुंचाया जाए।

इनका कहना है

यदि किसानों को पानी नहीं मिला तो सोडलपुर, मनियाखेड़ी, बरकला, कमताडा, दीपगांव, नहाली, बुंदडा, काथड़ी, गोदड़ी, करताना, नोसर, सकतापुर, डढांवाशंकर, खारपा, सुखरास, कनारदा, धुरगाड़ा के सैकड़ों किसान सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। जिसकी पूरी जबाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। पानी की कमी से किसी भी किसान की फसल सूखती है तो राज्य सरकार को सूखी हुई फसल का पूरा हर्जाना देना पड़ेगा।

बसंत रायखेरे और शैलेन्द्र वर्मा, भारतीय किसान यूनियन

सूख गए खिले फूल

किसान हो गया कर्जदार

सिवनी-मालवा। कोरोना संक्रमण इंसानी सेहत तो बिगाड़ ही रहा है। खेतों में खिले फूलों पर पर इसका बुरा असर पड़ा है। गोटियापुरा के आनंद बाथव ने करीब 2 लाख रुपए में जमीन खोट से ली। गेंदे सहित अन्य फूलों का बगीचा बनाया। आनंद के सपने थे कि फूल, माला बेचकर जो आमदनी होगी उससे परिवार का पालन पोषण करेंगे, लेकिन उनकी उम्मीदों का बगीचा उजड़ गया है। कोरोना कर्फ्यू के कारण न अच्छे से शादियां हो रही हैं न अन्य कार्यक्रम। बिक्री नहीं होने के कारण रंग-बिरंगे फूल सूख गए हैं। आनंद ने बताया करीब 2 लाख का कर्ज चढ़ चुका है। परिवार में वृद्ध मां, तीन बच्चे और पत्नी है।

मंडी बंद: 250 क्रेट टमाटर पशुओं को खिलाए

नरवाई जलाने से प्रदूषण और मिट्टी के समाप्त हो रहे पोषक तत्व

संवाददाता, रीवा

खेतों में नरवाई को किसान भले ही जलाकर उसकी सफाई का दावा कर रहे हों, लेकिन किसानों का यह कदम न सिर्फ पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है, बल्कि वे अपने जमीन के पोषक तत्व को समाप्त करने का भी काम नरवाई जलाकर कर रहे हैं। पर्यावरण को बचाने तथा जमीनों की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए किसानों को जगरूक होना पड़ेगा। गौरतलब है कि किसान खेतों में कटाई के बाद फसल के बचे हुए अवशेषों को जला देते हैं। जबकि कानून यह गलत है तो वही जमीनों के हिसाब से किसान नरवाई जालकर उसे खराब कर रहें है।

यह है नियम: नरवाई जलाने वाले किसानों को जिला प्रशासन की तरफ से धारा 144 के तहत कार्रवाई किए जाने का प्रावधान बनाया गया है। वहीं राज्य शासन के निर्देश के तहत जिला प्रशासन द्वारा नरवाई जलाने वाले ऐसे किसानों के खिलाफ2 से 5 हजार रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है।

नरवाई जलाने से यह होती है हानि: कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि नरवाई जलाने से प्रदूषण तो फैलता ही है। मृदा शक्ति कमजोर हो रही है। मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणु मौजूद रहते हैं। जिनसे मिट्टी में सांस लेने की शक्ति तैयार होती है तो वहीं ऐसे जीवाणु मिट्टी में खाद के रूप में काम करने के साथ ही उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का काम करते हैं। नरवाई जलाने से खेतों में मौजूद सूक्ष्म जीवाणु नष्ट हो जाते हैं जिससे खेत की जमीनों में हवा का आदान-प्रदान नहीं हो पाता है तो वहीं जीवाणु से जो खाद तैयार होती थी वह भी नहीं बन पाती है। यही वजह है कि खेतों की उर्वरा शक्ति समाप्त हो रही और इससे उत्पादन पर सीधा असर पड़ रहा है। नरवाई से उठने वाला धुंआ तथा उससे उड़ने वाले कचरे से पूरा वातावरण प्रभावित होता है।

» डीएपी के फिर बढ़ाए दामः 2400 होने की संभावना

» महीनेभर में मप्र सरकार ने दूसरी बार जारी की रेट लिस्ट

» 1200 में मिलने वाली बोरी के देने होंगे 1900 रुपए

प्रदेश में डीएपी खाद के रेट में 60 % इजाफा

संवाददाता, भोपाल

कोरोना महामारी के बीच किसानों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। अब सरकार के निर्णय ने उन्हें आर्थिक चोट दी है। संकट में फंसे अन्नदाताओं को अब 1200 रुपए में मिलने वाली डीएपी खाद के लिए 1900 रुपए चुकाने होंगे। यही नहीं, आगे 2400 रुपए प्रति बोरी होने की संभावना है। कुल मिलाकर डीएपी खाद के रेट में 60 फीसदी इजाफा किया गया है। विपणन संघ ने एक माह के भीतर दूसरा सर्कुलर निकालकर रेट लिस्ट जारी की है। मप्र राज्य सहकारी विपणन संघ ने हाल ही में नई रेट लिस्ट जारी की है। लिस्ट अनुसार डीएपी के खाद के दाम प्रति बोरी (50 किग्रा) 1900 रुपए हो गए हैं। इससे पहले 500 रुपए बढ़ाकर 1700 रुपए किए थे। खाद की बिक्री दरों का निर्धारण खरीफ 2021 के लिए उर्वरक समन्वयक समिति की बैठक में लिया गया। यह बैठक 07 मई 2021 को हुई थी। बैठक में लिए गए निर्णयों के संबंध में एक पत्र विपणन संघ एवं जिला सहकारी बैंकों के जिलाधिकारियों को जारी किया गया है।

इनका कहना है

डीएपी, यूरिया, पोटाश और काम्पलेक्स खाद का इंतजाम करने के लिए राज्य सहकारी विपणन संघ को नोडल एजेंसी बनाने का निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया गया। खाद का अग्रिम भंडारण पहले की तरह ही किया जाएगा।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, गृहमंत्री

मोदी शाह ने पेट्रोल-डीजल, डीएपी खाद और खाने के तेल की कीमतें बढ़ा दीं। कोरोना काल में जब आम आदमी परेशान है तो कोरोना से लड़ने के लिए सभी दवाइयों आदि पर से जीएसडी 31 मार्च 2022 तक तत्काल माफकर देना चाहिए।

दिग्विजय सिंह, पूर्व सीएम

यदि सरकार ने खाद की बढ़ी कीमतों को वापस नहीं लिया, तो सीएम हाउस के सामने धरना देंगे। सरकार ने खाद की कीमतों में बढ़ोतरी कर किसानों पर एक बोझ और डाल दिया है। डीएपी व एनपीके की कीमत 1200 से 1900 रुपए करने को न्यायोचित नहीं माना जा सकता।

जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री

सहकारी समितियों के पास पूर्व भंडारित डीएपी खाद का स्टॉक है। जो कि पूर्व की दरों यानि 1200 प्रति बोरी में ही बिकेगा। यह दरें आगामी खरीफसीजन के लिए निर्धारित की गई हैं। नया स्टॉक नई दरों पर बिकेगा।

रोहित कुमार श्रीवास्तव, जिला विपणन अधिकारी, खंडवा

लगातार रासायनिक उर्वरक खाद के भाव में बढ़ोतरी हो रही है। बात तो किसानों की आय दोगुनी करने की थी, इसके उलट आय दोगुनी तो नहीं हुई, बल्कि किसानों की लागत में बढ़ोतरी की जा रही है। बढ़े हुए दाम तत्काल वापस लेना चाहिए। किसान तो वैसे भी देसी खाद का उपयोग कर रहे हैं।

अनिल कुमार मिश्रा, किसान

2014 से पहले पीएम नरेंद्र मोदी किसानों की आय दोगुना करने का वादा करते थे। सत्ता में आने के बाद भी यह जारी रहा। नए कृषि कानूनों के खिलाफ 5 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में अब उर्वरकों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। जब सरकार कह रही है कि जैविक खाद का रकबा बढ़ रहा है तो डीएपी के दाम अचानक क्यों बढ़ा दिए गए।

राघवेंद्र द्विवेदी, किसान

अश्वगंधा की खेती से किसान हो रहे आत्मनिर्भर

संवाददाता, विदिशा

कोरोना महामारी में जहां एक ओर देश की अर्थव्यवस्था डामाडोर नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर संक्रमितों के लिए इम्युनिटी बूस्टर बनी आयुर्वेदिक औषधि अश्वगंधा की खेती मप्र के किसानों को आत्मनिर्भर बना रही है। यही नहीं, मांग बढ़ने से किसानों को 16 गुना तक मुनाफा भी हो रहा है। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली आयुर्वेदिक औषधि अश्वगंधा कोरोना महामारी के दौरान मप्र के विदिशा जिले के किसानों को मालामाल कर रही है। विदिशा जिले के 40 गांवों में बड़े पैमाने पर अश्वगंधा की खेती हो रही है। महामारी में अश्वगंधा की मांग बढ़ने से किसान लागत से 16 गुना मुनाफा कमा रहे हैं। इस बार कंपनियां फसल खरीदने के लिए किसानों से संपर्क कर रही हैं। इस वजह से किसानों की परिवहन की लागत कम हुई है और पिछले साल से मुकाबले दोगुना कीमत मिल रही है। विदिशा जिले के कुछ गांवों में पिछले सात साल से किसान अश्वगंधा की खेती कर रहे हैं।

40 हजार रुपए प्रति क्विंटल

पाली गांव में लंबे समय से अश्वगंधा की खेती कर रहे किसान लखन पाठक बताते हैं कि कोरोना की दसरी लहर में अश्वगंधा की भारी मांग है। इस बार भाव भी पिछले साल की तुलना में दोगुना मिल रहे हैं। पिछले साल 20 हजार रुपए क्विंटल में अश्वगंधा बेची थी। इस बार 40 हजार रुपए प्रति क्विंटल भाव हैं।

कंपनियां खुद आकर खरीद रहीं

अभी मंडी बंद है तो आयुर्वेदिक कंपनियां सीधे किसानों से संपर्क कर रही हैं। इससे फसल के परिवहन पर खर्च होने वाली रकम भी बच रही है। खेत से फसल निकल रही है। जड़ों को सुखाने के बाद इन्हें बेचा जाएगा। ग्राम मोही के किसान बलवीर सिंह बताते हैं कि उनके लिए अश्वगंधा की खेती फायदे का धंधा बन गई है। इसमें परंपरागत फसलों से ज्यादा मुनाफा है।

लागत कम और मुनाफा ज्यादा

काकरखेड़ी के किसान श्यामलाल शर्मा का दावा है कि अश्वगंधा की खेती में एक बीघा में अधिकतम छह हजार की लागत लगती है, जबकि पैदावार दो से ढाई क्विंटल होती है। यानी एक बीघा में एक लाख की औषधि प्राप्त हो रही है और 16 से 17 गुना मुनाफा हो रहा है। अश्वगंधा की फसल पांच से छह माह की होती है। इसका बीज 100 रुपए प्रति किलो मिलता है। एक बीघा में अधिकतम 10 किलो बीज लगता है। अश्वगंधा की जड़ों से आयुर्वेदिक दवा बनती है। वहीं पत्तों से भंसा बनता है। यह भूसा भी दो से तीन हजार रुपए क्विंटल बिकता है।

फायदेः रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। बलवर्द्धक और स्फूर्तिदायक होता है। तनाव मुक्त करता है। स्मरणशक्ति भी बढ़ाता है।

इनका कहना है

अश्वगंधा औषधि के कई फायदे हैं, लेकिन यह ऐसी दवा है जिसे बिना आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर औषधि की मात्रा और इसे लेने के सही तरीके की जानकारी देते हैं।

डॉ. अनिल अग्रवाल, वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक, विदिशा

कम लागत में अधिक मुनाफा होने के कारण विदिशा जिले में अश्वगंधा की खेती की ओर किसानों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। जिले में अभी करीब 40 गांवों में 400 एकड़ में अश्वगंधा की खेती हो रही है।

केएल व्यास, जिला उद्यानिकी अधिकारी, विदिशा

आवश्यकता

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर और मुरैना से प्रकाशित

जागत गांव हमार

कृषि और पंचायत पर आधारित साप्ताहिक समाचार पत्र के लिए जिला, जनपद स्तर पर संवाददाता चाहिए।

संपर्क करें

कार्यालय का पताः- लाजपत भवन प्रथम तल, आईसीआईसीआई बैंक के पास, एमपी नगर, जोन-1, भोपाल, मप्र.
संपर्क करें- 07554064144, 9229497393, 9425048589

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, म.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादकः अजय कुमार द्विवेदी, संपर्क-9229497393, 9425048589, ईमेलः- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)